Need to declare Eastern Rajasthan Canal Project as a national project-Laid

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैं प्रधानमंत्री जी और जलशक्ति मंत्री का ध्यान राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल तथा सिंचाई से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की तरफ आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि ईआरसीपी के माध्यम से राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर जिले में राहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा वर्तमान सिंचित क्षेत्र का कायाकल्प करने व 2 लाख हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है । राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय जल आयोग ने दिल्ली द्वारा इस परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 6 अक्टूबर 2016 को दी है क्योंकि यह पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए जीवन दायिनी परियोजना है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए यदि किसी निर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार से प्रस्ताव लेने की आवश्यकता है तो स्वयं केंद्र इसमें पहल करके जनहित में यह प्रस्ताव मंगवाए क्योंकि किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है । राजस्थान की जनता लंबे समय से यह मांग भी कर रही है तथा इस विषय पर मेरा यह भी आग्रह है कि राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य पानी को लेकर कोई विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसका समाधान भी जनहित में केंद्र सरकार को आगे जाकर करने की जरूरत है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें मानसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, काली, सिंध तथा मेज नदी के अधिशेष पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती व काली सिंध नदियों में पहुंचाने की परिकल्पना की गई है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि बिना किसी भेदभाव के केंद्र

सरकार को जल्द से जल्द ईआरसीपी को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करनी चाहिए ।